



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2015/ज्येष्ठ 4, 1937

No. 180]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2015/JYAISTHA 4, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 18 मई 2015

सं. टीएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च, 2005 को आदेश सं. टीएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता आगे विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मई, 2015 के 15 वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 39 द्वारा 31 मार्च 2005 को 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च, 2005 से लागू हुए थे और दिशानिर्देशों के खंड 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी बनाए रखा गया था जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा अथवा विस्तार नहीं किया जाता है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, यह प्राधिकरण 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता समय-समय पर विस्तारित करता रहा है और 31 दिसम्बर, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आखिरी विस्तार हमारे आदेश दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा 20 अक्टूबर, 2014 को जी.सं. 295 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नीति, 2015" नामक महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा जारी की थी और प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से तदनुसार कार्य करने का निदेश दिया था। तदनुसार, 'महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नीति, 2015' नामक महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति 27 जनवरी, 2015 को राजपत्र सं. 30 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में अधिसूचित की गई थी। उक्त महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2015 तत्काल अर्थात् 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी हो गई थी, जैसा कि एमओएस द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा निदेश दिया गया था।

4. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी (पीटी-II) दिनांक 2 जनवरी, 2015 द्वारा (हमें 18 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुआ) 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च 2015 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया है।

5. तदनुसार, 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता निम्न के लिए विस्तारित की गई है –
- (i) महापत्तन न्यास 1 जनवरी, 2015 से 12 जनवरी, 2015 तक; और,
- (ii) वर्तमान में 2005 दिशानिर्देशों के अधीन शासित महापत्तनों में प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनल प्रचालकों के लिए, 1 जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2015(74)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 18th May, 2015

No. TAMP/41/2009-WS.— In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified vide Order No.TAMP/23/2003-WS on 31 March, 2005, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/41/2009-WS

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 15th day of May, 2015)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March, 2005 vide Gazette No.39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March, 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, remained in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March, 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2. As advised by the Government of India in the Ministry of Shipping this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time and the last extension till 31 December, 2014 or until further orders, whichever is earlier, was notified in the Gazette of India on 20 October, 2014 vide G.No.295 vide our Order dated 8 October, 2014.

3. In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January, 2015 issued a Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed the Authority to Act accordingly with immediate effect. Accordingly, the Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 27 January, 2015 vide Gazette No.30. The said Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015 came into immediate effect i.e. from 13 January, 2015, as directed by the MOS vide its letter dated 13 January, 2015.

4. The Government of India in the Ministry of Shipping, vide its letter No. PR-14019/20/2009-PG(pt-II) dated 2 January, 2015 [received by us on 18 April, 2015], has extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' till 31 March, 2015 or until further orders, whichever is earlier.

5. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is extended for –

- (i) Major Port Trusts from 1 January, 2015 to 12 January, 2015; and,
- (ii) For Private Terminal Operators operating at Major Ports presently governed under 2005 guidelines from 1 January, 2015 to 31 March, 2015 or until further orders, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. – III/4/Ext./143/2015 (74)]